सेवामें,

दि. 27.7.99

उप सचिव (ओ. एण्ड एम.)
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग,
नई दिल्ली ।

विषय : प्रशासनिक खर्चों में कमी हेतु सुझाव

सन्दर्भ : आपका विज्ञापन (जुलाई - 99)

मान्यवर,

भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रशासनिक विभागों, अभिकरणों, आयोगों, बोर्डों तथा संस्थानों द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक रिपोर्ट या अर्ध प्रगतिप्रतिवेदन तैयार किया जाता है । इसी प्रकार विभागीय पत्र-पत्रिकाएँ भी मासिक प्रकाशित होती हैं ।

इन वार्षिक प्रतिवेदनों या मासिक पत्रिकाओं का कागज अत्यंत महंगा, चिकना, रंगीन होता है जो प्रशासन पर अनावश्यक बोझ डालता है। यदि साधारण कागज पर इनका मुद्रण करवायें तो यह व्यय आधा हो सकता है। इसी प्रकार क्रम में एक सुझाव यह भी है कि प्रशासनिक प्रतिवेदन, समिति/आयोग रिपोर्ट तथा आंकड़े सभी विभागों के किसी एक स्थान पर नियमित मिलें तथा क्रेता से मूल्य (कीमत) वसूल की जाए । सरकारी प्रतिवेदनों की उपलब्धता कम है साथ ही वे नि:शुल्क हैं अत: एक सार्थक नीति बनाएँ जिसमें सस्ता कागज काम में लें, जनता को वह रिपोर्ट शुल्क उपलब्ध करायें ।

सादर

भवदीय

S. Kataria

(डॉ. सुरेन्द्र कटारिया)
पोस्ट बॉक्स नं. 20
सीकर - 332001 राज.

Scanned with OKEN Scanner